प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

1 A	→ इसके द्वारा पहली बार कम्पनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता।
	→ बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद → कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना
1 B	→ संविधान सभा के लिये कानूनी सलाहकार।
1 C	→ सर. ए. पालकीवाला
1 D	→ 1973 में उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले के तहत कई ऐतिहासिक निर्णय दिये गये
	→ सबसे महत्वपूर्ण "संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत"
1 E	→ अनुच्छेद 39A संविधान के भाग 4 के तहत नीति निदेशक सिद्धांत का हिस्सा है।
	→ यह समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है।
	→ राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्थापना अनु. 39A के पालन हेतु की गई
1 F	→ मूल संविधान में 14 भाषाओं को शामिल किया → 31 वाँ संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को 15 वीं भाषा → वर्तमान में 8 वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ शामिल है।

Scanned with CamScanner

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

1 J	→ 1986 में पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार के लिये सिंघवी समिति का गठन
	→ पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता देने एवं संरक्षण हेतु सिफारिश
...	..
1 H	→ बर्लिन (जर्मनी) स्थित गैर लाभकारी संस्थान → भ्रष्टाचार से संबंधित इंडेक्स जारी करती है।
	→ भारत की 2020 में भ्रष्टाचार सूचकांक में रैंक - 80वीं
1 I	→ एक मंच है, जिसमें विवादों का निपटारा सौहार्दपूर्ण ढंग से होता है।
	→ राष्ट्रीय चिकित्सा सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के द्वारा वैधानिक दर्जा मिला
	→ अंतिम फैसला सभी पक्षों पर बाध्यकारी, कोई अपील नहीं की जा सकती
	..
1 J	→ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत गठित → आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, एक समिति की सिफारिस पर → कार्य - सूचना संबंधी शिकायतों की जांच

Scanned with CamScanner

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

1 K
→ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा व समाधान हेतु संसद के स्तर पर स्थापित मंच है।
→ अध्यक्ष - लोकसभा अध्यक्ष
→ वर्तमान में 8 मंच स्थापित है।

1 L
→ अमेरिकी संविधान से प्रेरित
→ न्यायपालिका द्वारा विधायी कानूनों की समीक्षा, स्वयं संज्ञान के माध्यम से
→ ~~...~~

1 M
→ राष्ट्रपति के अभिभाषण के तुरंत बाद सदन में यह प्रस्ताव चर्चा हेतु लाया जाता है।
→ सरकार अपनी नीतियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करती है।
→ चर्चा के बाद मतदान के लिये रखा जाता है

1 N
1993 ई में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया।

1 O
→ भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के प्रशिक्षण हेतु सर्वोच्च संस्थान
→ मसूरी, उत्तराखण्ड में स्थित।

Scanned with CamScanner

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

2 A

सरकारी विधेयक	गैर सरकारी विधेयक
① सदन में मंत्री द्वारा पेश किया जाता है।	1. मंत्री के अलावा कोई भी सदस्य पेश कर सकता है।
2. सरकारी नीतियों से संबंधित होता है।	2. सार्वजनिक मामलों में विपक्षी दल का रुझान व्यक्त करता है।
3. पेश करने से पूर्व 7 दिन का नोटिस	3. पेश करने से पहले एक माह का नोटिस आवश्यक
4. संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार होता है।	4. पेशकर्ता सदस्य की पूरी जिम्मेदारी
5. पारित न होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है (अविश्वास को प्रकट करता है)	5. यह विधेयक अस्वीकृत होने पर सरकार पर प्रभाव नहीं पड़ता।

KAUTILYA ACADEMY INDORE

Scanned with CamScanner

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

2 B

अनुच्छेद 33; भारतीय संविधान में भाग 3 के तहत प्रदान किये गये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है।

यह अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि वह सेना, अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर युक्त-युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। प्रयुक्त शब्द "सैन्य बलों के सदस्य" में सेना के वे कर्मचारी भी शामिल है जो नाई, बढ़ई, दर्जी, बावर्ची, मूची पालिस आदि कार्य करते है।

अनुच्छेद 33 का उद्देश्य सेना में समुचित कार्य के साथ अनुशासन बनाये रखना है। इसके साथ ही संसद द्वारा इसके तहत बनाये गये किसी भी कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, चाहे चुनौती का आधार मूल अधिकारों का उल्लंघन ही क्यों न है।

संसद ने 1950 में पारित सैन्य अधिनियम, नौसेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950 तथा पुलिस बल (अधिकार विस्तार) अधिनियम, 1966 इसी अनुच्छेद 33 के दायरे से निर्मित किये है।

Scanned with CamScanner

2 C

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति देता है। वित्तीय संकट की अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं।

1. केन्द्र सरकार किसी राज्य को वित्तीय सिद्धांतों के पालन का निर्देश दे सकती है।

2. राष्ट्रपति वेतन, भत्तों में कटौती के निर्देश जारी कर सकता है जिनमें शामिल हैं: केन्द्रीय सेवा में कार्यरत सभी श्रेणियों के कर्मचारी, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश

3. राज्य की सेवा में सभी श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती

4. राज्य विधायिका के सभी विधेयक और वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखना होता है।

अतः वित्तीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य की वित्तीय गतिविधियों पर पूर्णतः केन्द्र का नियंत्रण हो जाता है।

KAUTILYA ACADEMY INDORE

Scanned with CamScanner

भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार..

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

प्रश्न संख्या: 2 D

प्राक्कलन समिति संसद की स्थायी वित्तीय समिति है। यह लोकसभा की सबसे बड़ी समिति भी है।

यह समिति 30 सदस्यों से मिलकर बनी होती है जिसके सभी सदस्य लोकसभा से संबंधित होते हैं और चुनाव भी लोकसभा सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति से होता है। लोकसभा में दलों की आनुपातिक संख्या के आधार पर उन्हें प्राक्कलन समिति में प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है प्रतिवर्ष चुनाव कराये जाते हैं। अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से होता है। सरकार का कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता।

प्राक्कलन समिति का कार्य बजट में सम्मिलित प्राक्कलनों की जाँच और सार्वजनिक व्यय के नियंत्रण में सुझाव देना होता है। इसीलिये इसे "सतत किफायत समिति" भी कहते हैं।

KAUTILYA ACADEMY INDORE

Scanned with CamScanner

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

2 F

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसम्बर 1986 को ~~संसद द्वारा अधिनियमित~~ लागू हुआ। यह कानून उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है इस हेतु उपभोक्ता विवादों के त्वरित निपटान के लिये त्रिस्तरीय ~~अर्द्ध~~ न्यायिक व्यवस्था का प्रावधान भी किया है।

हाल ही में संसद ने उपभोक्ता ~~अधिकार~~ संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2019 को लागू किया है जिसमें उपभोक्ता न्यायालयों के स्वरूप में कुछ परिवर्तन किये हैं। जिला फोरम अब जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग; जो जिला स्तर पर होगा और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग स्थापना का प्रावधान है। ~~जिला आयोग के निर्णय के~~ इन आयोगों के फैसले की अंतिम अपील केवल उच्चतम न्यायालय के समक्ष ही की जा सकेगी।

जिला स्तरीय आयोग – 1 करोड़ तक के मामले की सुनवाई
राज्य स्तरीय आयोग – 1 करोड़ से अधिक – 10 करोड़ तक
राष्ट्रीय आयोग – 10 करोड़ से अधिक के मामले

संशोधित कानून 1 केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करता है जो उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा हेतु स्वतः संज्ञान के रूप में उपभोक्ताओं की ओर से न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।

Scanned with CamScanner

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

2 H

संघीय व्यवस्था से तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें शक्तियों का विभाजन सरकार के विभिन्न स्तरों पर होता है जिसका वे स्वतंत्रतापूर्वक प्रयोग करते हैं। भारतीय संविधान में संघीय तत्वों को 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिये गये हैं।

विशेषताएँ

- द्वैध सरकार - भारत में केन्द्र व राज्य स्तर पर संघीय शक्तियाँ दी गई हैं।
  - → केन्द्र के लिये राष्ट्रीय महत्व के विषय
  - → राज्य के लिये क्षेत्रीय महत्व के विषय
- शक्तियों का पृथक्करण - केन्द्र व राज्य के बीच 7 वी अनुसूची में अल्लिखित शक्ति विभाजन
- → संविधान की सर्वोच्चता
- → स्वतंत्र न्यायपालिका
- → द्विसदनीयता
- → कठोर संविधान
- → लिखित संविधान

भारतीय संघ की विशेषताओं में 2 महत्वपूर्ण बातें है जो

1. भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है।
2. राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।

KAUTILYA ACADEMY INDORE

Scanned with CamScanner

भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार...

प्रश्न संख्या 2 I

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान के तहत उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बना है। परंतु शक्ति व कार्यों के आधार पर पर्याप्त भिन्नता है।

भारत में उपराष्ट्रपति	अमेरिका में उपराष्ट्रपति
↓	↓
1. राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब तक कि नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता	राष्ट्रपति पद के रिक्त होने पर शेष अवधि के लिए राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है।
2. उपराष्ट्रपति का पद मात्र राजनीतिक निरंतरता बनाए रखने के लिए होता है।	उपराष्ट्रपति को विशेष कार्य सौंपे जाते हैं।
3. परिलब्धियाँ व वेतन राज्यसभा का सभापति होने के कारण प्राप्त होते हैं।	अलग से उपराष्ट्रपति के वेतन-भत्ते प्राप्त हैं।
4. उच्च सदन का सभापति होता है।	स्वतंत्र पद स्थापित है।

KAUTILYA ACADEMY INDORE

Scanned with CamScanner

2 J

भारत में राज्यपाल को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई विवेकाधीन शक्तियाँ प्राप्त हैं।

विवेकाधिकार शक्तियाँ

प्रत्यक्ष संवैधानिक

- राष्ट्रपति के विचार हेतु विधेयकों का आरक्षित रखना
- राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश
- असम, मेघालय, त्रिपुरा मिजोरम में राज्यपाल द्वारा जनजातीय जिला परिषदों को देय राशि का निर्धारण (6वीं अनुसूची)
- प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी लेना

अप्रत्यक्ष पारंपरिक

- विधानसभा में पूर्ण बहुमत न मिलने पर गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना
- अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार/मंत्रिपरिषद को बरखास्त करना
- मुख्यमंत्री की सिफारिश पर विधानसभा को विघटित करना

इस प्रकार राज्यपाल द्वारा विवेक का प्रयोग करने लिए गये निर्णयों पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता इस संदर्भ में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है।

Scanned with CamScanner

भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार...

प्रश्न संख्या 3 A

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

भारत की आंतरिक सुरक्षा पर खतरा डालने वाले संगठनो को क्षेत्रीय व प्रभुत्व के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है जो निम्नलिखित है।

→ आतंकवादी संगठन
→ वामपंथी / उग्रवादी संगठन
→ अलगाववादी संगठन (जम्मू कश्मीर)
→ पूर्वोत्तर राज्यो में उग्रवादी संगठन

वर्तमान में दुनिया भर में आतंकवाद एक ~~मानव अस्तित्व~~ बड़ा खतरा बन कर उभरा है। भारत सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम 1967 के तहत प्रथम अनुसूची में कई संगठनो को आतंवादी गुट के रूप में शामिल किया है-

① अलकायदा - भारतीय उपमहाद्वीप में सक्रिय

② इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएस आईएस)
- खुरासान प्रांत में सक्रिय एवं इससे संबंधित सभी संगठन

③ खालिस्तान लिबरेशन फोर्स तथा इसके सभी संगठन

④ तहरीक-उल-मुजाहिद्दीन

Scanned with CamScanner

भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार...

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

भारत के कई राज्यों में वामपंथी गतिविधियों के कारण कानून एवं व्यवस्था को निरंतर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वामपंथी संगठनों में ~~देश~~ ~~के~~ ~~विभिन्न~~ सीपीआई (माओवादी) सबसे प्रभावी संगठन है। कुल हिंसक घटनाओं में 88% हिंसा सीपीआई द्वारा संचालित होती है। वर्तमान में इसका विस्तार 10 राज्यों में सर्वाधिक है।

भारत सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 के तहत सीपीआई को आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया है।

जम्मू कश्मीर में सीमापार से प्रयोजित अलगाववादी गतिविधियों में जैश-ए-मुहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों का हाथ होता है। आये दिन कश्मीर में होने वाली पत्थरबाजी की घटनायें इनका उदाहरण है।

हालांकि सरकार के प्रयासो से शांति व्यवस्था में ~~तैनात~~ ~~जवानों~~ ~~और~~ ~~जैसे~~ की दिशा में कई योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है।

इसी प्रकार पूर्वोत्तर भारत के आठ राज्यों में कई उग्रवादी समूह सक्रिय हैं जिनमे अरुणाचल प्रदेश मे नागालैण्ड आधारित एनएससीएन (~~सबसे~~ नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड) तथा असम आधारित उल्फा की आतंकवादी गतिविधियाँ शामिल है।

Scanned with CamScanner

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार..

असम का उग्रवादी समूह यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैण्ड आदि हिंसात्मक गतिविधियों में संलिप्त है इन्हें भी भारत सरकार द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है।

अन्य राज्यों कुछ स्वदेशी विद्रोही समूहों का भी आतंक फैला हुआ है। मेघालय में गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी, हिन्नीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल सक्रिय संगठन है। त्रिपुरा में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, और त्रिपुरा टाइगर फोर्स अपहरण व हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देकर अशांति और भय का माहौल निर्मित करते हैं।

इस प्रकार अलग-अलग जातीय बहुलता और क्षेत्र में जटिल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये केन्द्र सरकार राज्य की सरकारों से मिलकर ऐसे दलों से त्रिपक्षीय वार्ता करती है जिससे शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को मुख्य धारा में लाया जा सके।

हाल में भारत सरकार ने बोडो समूह से समझौता किया है। साथ ही सशस्त्र बलों की तैनाती, सीमापार घुसपैठ को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक फेंसिंग जैसे सुरक्षा उपायों को अपनाकर देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा रहा है।

Scanned with CamScanner

3 B

"नारी नर की खान है नर से बढ़कर नारी"

महिला घरेलू हिंसा से तात्पर्य ऐसे कृत्यों से जिनमें चारदीवारी के भीतर किसी महिला के साथ मारपीट, गाली-गलौज, भावनात्मक तथा शारीरिक उत्पीड़न, दहेज की मांग के लिये हिंसा को अंजाम दिया जाता है। अधिकतर यह उत्पीड़न पुरुषों द्वारा किया जाता है, परंतु कई बार मामलों में पूरा परिवार भी शामिल होता है।

ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने अगस्त 2005 में एक विधेयक को पारित किया जो घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम, 2005 के नाम से जाता है। यह कानून वर्तमान में संपूर्ण भारत में लागू है।

इस कानून के तहत महिलाओं को कई प्रकार से घरेलू हिंसा से संरक्षण प्राप्त है। 2005 में लागू इस कानून में 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं।

किसी भी पुरुष के साथ रह रही महिला यदि घरेलू उत्पीड़न का शिकार होती है तो इस अधिनियम के तहत वह अपराधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है। कानून के महत्वपूर्ण प्रावधानों में गाली मारना, शारीरिक दोन शोषण, भावनात्मक तथा आर्थिक शोषण यहाँ तक कि महिला को धमकी देना

Scanned with CamScanner

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

अपराध की श्रेणी में आता है। यह कानून महिलाओं के स्त्रीत्व तथा गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को सुरक्षित करता है। साथ ही जिस घर में महिला रहती है, उसे वहाँ से निकाला नहीं जा सकता; एक महत्वपूर्ण बिंदु को शामिल करता है।

समाज में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा को कम करने में यह कानून एक महत्वपूर्ण विकल्प के तौर पर उपलब्ध है हालांकि जागरूकता में कमी तथा प्रचार-प्रसार न होने के कारण घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम अधिक प्रभावी नहीं हो पाया है।

घरेलू हिंसा की रोकथाम अधिनियम 2005 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल है।

धारा 1 - अधिनियम का संक्षिप्त नाम
घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधि. 2005
होगा, विस्तार - सम्पूर्ण भारत (2020 से)

धारा-3 घरेलू हिंसा को परिभाषित किया है।
जिसमें शारीरिक, लैंगिक, मानसिक हिंसा शामिल है।

धारा-5 - पुलिस अधिकारियों में मजिस्ट्रेट के कर्त्तव्य का उल्लेख

धारा-6 - आश्रय गृह के कर्त्तव्यों को बताया

Scanned with CamScanner

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार..

धारा-7 मे पीड़ित के चिकित्सकीय सहायता संबंधी प्रावधान है।

धारा 12 मे पीड़ित महिला द्वारा मजिस्ट्रेट को आवेदन संबंधी प्रावधान तथा धारा-14 में पीड़ित को परामर्श लेने संबंधी प्रावधान।

समाज की प्रकृति को ध्यान मे रखते हुये धारा 16 मे कार्यवाहियो की सुनवाई को बंद कमरे मे किये जाने का प्रावधान है। जबकि धारा-17 में असहाय महिला को निवास का अधिकार दिया गया है। धारा-19 मे निवास की सुविधाओ को उपलब्ध कराया जायेगा तथा धारा 20 मे आर्थिक सहायता दी जायेगी।

पीड़ित महिलाओ मे ऐसी महिलाओ को भी शामिल किया है जो विधवा हो या अकेले रहने को विवश है। लिव इन रिलेशन मे बिना विवाह के रह रही महिला को भी इस कानून मे संरक्षण प्राप्त है।

सभी महिलाओ के विरुद्ध घरेलू अपराध दंडनीय होने के साथ-साथ गैर जमानतीय भी है। दण्ड में 1 वर्ष की कैद, जो 20 हजार रुपये के जुर्माना सहित भी हो सकती है।

धारा-29 मे अपील संबंधी प्रावधान है और धारा-37 मे केन्द्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति है।

Scanned with CamScanner

महिलाओं को घरेलू हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाने में यह कानून एक शक्तिशाली हथियार है परंतु समुचित जानकारी, अशिक्षा के कारण यह आम लोगो तक अपनी पहुँच स्थापित करने में सफल नहीं हो पाया है, जरूरत इस बात की है कि गैर सरकारी संगठनों महिला कार्यकर्ताओं व सरकारी प्रयासो से इस कानून को प्रत्येक परिवार जानना चाहिए तभी सही मायने में इसके अस्तित्व का उद्देश्य पूरा हो सकेगा और समाज महिला के सम्मान, गौरव को पुनः स्थापित किया जा सकेगा।

KAUTILYA ACADEMY INDORE

Scanned with CamScanner